भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5268

उत्तर देने की तारीख-03/04/2023

महामारी के कारण बच्चों में सीखने की कमी

†5268. डॉ. के. जयकुमारः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महामारी के कारण बच्चों में सीखने की कमी में वृद्धि का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में मूलभूत पठन और अंकगणितीय क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्हें विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ङ): कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण, छात्रों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इससे प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधीन हैं। महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनेक विचार-विमर्श किए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा तीन साल की चक्र अवधि के साथ कक्षा III, V, VIII और X पर केन्द्रित नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। एनएएस का अंतिम दौर 12 नवंम्बर, 2021 को पूरे भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के छात्र शामिल थे। एनएएस का लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के दक्षता सूचकांक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमता का मूल्यांकन करना है ताकि विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्यों के लिए समुचित कदम उठाए जा सकें। एनएएस 2021 के लिए राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला रिपोर्ट 25.05.2022 को प्रकाशित की गई हैं और http://nas.gov.in पर उपलब्ध हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों के प्रभाव को कम करने और ड्रॉप आउट्स, कम नामांकन और अधिगम में होने वाली हानि को रोकने के लिए प्रवासी बच्चों की

पहचान, सुचारू प्रवेश प्रक्रिया और सतत शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 13.07.2020 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को गुणवत्ता और समता के साथ शिक्षा प्राप्त हो और देश में स्कूल शिक्षा पर महामारी का कम से कम प्रभाव हो, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर व्यापक दिशा-निर्देश 7 जनवरी, 2021 को तैयार और जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में अन्य के साथ-साथ, स्कूल न जाने वाले 6-18 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता सृजन, स्कूल बंद होने पर छात्र सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) के लिए निरंतर शिक्षा, फिर से स्कूल खुलने पर छात्र सहायता और शिक्षकों का क्षमता निर्माण शामिल है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अधिगम हानि को कम करने के लिए दिनांक 4 मई 2021 के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हित धारकों के साथ एक व्यापक कोविड कार्य योजना साझा की थी।

पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी जिसमें शिक्षा तक मल्टी मोड पहुंच बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत किया गया है। पहल में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए दीक्षा राष्ट्र की डिजिटल अवसंरचना (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)।
- कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित एक पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट-शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग
- डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में नेत्रहीन और श्रवण बाधितों के लिए विकसित विशेष ई-सामग्री

जहां डिजिटल सुविधा (मोबाइल डिवाइस/डीटीएच टेलीविजन) उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने कई पहल की हैं जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट, शिक्षार्थियों के घर पर आपूर्ति की गई पाठ्यपुस्तकें, वर्कशीट, 21वीं सदी के कौशल पर हैंडबुक उपलब्ध कराई गई और समुदाय/मोहल्ला कक्षाएं आयोजित की गई थीं। विभाग के नवाचार कोष का उपयोग मोबाइल स्कूल/वर्चुअल स्टूडियो/स्कूलों में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने के लिए किया गया था, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सतत अधिगम योजना (सीएलपी) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई थी, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के तहत प्री-लोडेड टैबलेट का उपयोग दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से किया जाता है जहां ऑनलाइन कक्षाएं कठिन होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए, इस विभाग ने अक्टूबर 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। प्रारंभिक स्तर के लिए निष्ठा ऑनलाइन में 11 भाषाओं में 18 मॉड्यूल शामिल हैं, जिसमें शिक्षण-अधिगम में आईसीटी का उपयोग शामिल है।

*****